UPI पर MDR की बहस: भुगतान का खर्च कौन उठाए

समाचार-संदर्भ: 2026-11-05 | **प्रकाशन:** 7 नवंबर 2026

मुख्य परीक्षा: GS-III: डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और सार्वजनिक नीति



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

12 नवंबर 2026 का अपडेट: दीपावली के दो दिन बाद भी MDR लागू करने की तारीख का ऐलान नहीं

द हिंदू की 12 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार **NPCI ने अभी तक UPI पर MDR लागू करने की तारीख घोषित नहीं की है**। लगभग एक महीने पहले NPCI ने मूल **15 अक्टूबर** की समय-सीमा आगे बढ़ाते हुए कहा था कि MDR "दिवाली के तुरंत बाद" लागू होगा, परंतु दीपावली बीतने के दो दिन बाद भी घोषणा लंबित है।

अर्थात MDR विवाद में स्थिति यथावत है - शुल्क-भार किस पर पड़ेगा और अंतिम लागत-संरचना क्या होगी, यह सवाल अभी खुला है; परीक्षा की दृष्टि से यह 'चालू नीति-विकास' के रूप में नोट करें।

खबरों में क्यों

5 नवंबर 2026 की न्यायालय-संबंधी रिपोर्ट में केंद्र ने UPI के कुछ व्यापारी भुगतानों पर प्रस्तावित **मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR)** का समर्थन करते हुए डिजिटल भुगतान-तंत्र की लागत और उसकी दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरता का प्रश्न उठाया। रिपोर्ट के अनुसार केंद्र का हलफनामा 4 नवंबर को दाखिल हुआ था। यह सरकार का पक्ष है, न्यायालय का अंतिम निर्णय नहीं।

NPCI के **13 अक्टूबर 2026** के आधिकारिक वक्तव्य में चयनित व्यक्ति-से-व्यापारी भुगतानों पर MDR को दीपावली के बाद, अलग से अधिसूचित तारीख पर लागू करने की बात है। उस वक्तव्य से कोई निश्चित आरंभ-दिन या सभी UPI भुगतानों पर शुल्क लागू होने का निष्कर्ष नहीं निकलता।

MDR क्या है

MDR भुगतान स्वीकार करने की सेवा के लिए व्यापारी से लिया जाने वाला शुल्क है। डिजिटल भुगतान में बैंक, भुगतान सेवा-प्रदाता और अन्य प्रतिभागी तकनीकी तथा परिचालन सेवाएँ देते हैं। ग्राहक को हर लेनदेन पर अलग बिल न दिखने से तंत्र की वास्तविक लागत शून्य नहीं हो जाती।

P2M का अर्थ व्यक्ति से व्यापारी को भुगतान है। **P2P** व्यक्ति से व्यक्ति को भुगतान है। चयनित P2M पर प्रस्ताव को सामान्य व्यक्ति-से-व्यक्ति हस्तांतरण या हर QR भुगतान पर एकसमान नया कर न बताएं। MDR स्वयं कर का पर्याय भी नहीं है।

सरकार का तर्क और स्थिति की सीमा

समाचार-रिपोर्ट के अनुसार केंद्र ने कहा कि कम मूल्य और छोटे व्यापारियों की सुरक्षा के साथ अधिक मूल्य वाले कुछ व्यापारी भुगतानों से लागत जुटाना तर्कसंगत हो सकता है। रिपोर्ट में 2,000 रुपये तक के P2M लेनदेन को छूट देने की बात सरकार के पक्ष के रूप में आई है।

किसे, कितनी दर से और कब शुल्क देना होगा, इसका अंतिम निष्कर्ष संबंधित अधिसूचना और लागू नियमों से ही निकलेगा। उपलब्ध NPCI वक्तव्य दरों का पूरा विवरण नहीं देता। इसलिए इस लेख से किसी ग्राहक या व्यापारी को अपने वास्तविक बैंक शुल्क का अनुमान नहीं लगाना चाहिए।

NPCI का पक्ष: ग्राहक पर MDR न डालने का निर्देश

5 नवंबर 2026 की न्यायालय-संबंधी रिपोर्टों के अनुसार NPCI ने 3 नवंबर को दाखिल जवाबी हलफनामे में कहा कि व्यापारी MDR को ग्राहक पर नहीं डाल सकते और UPI ऐप-प्रदाता भुगतान के लिए प्लेटफॉर्म शुल्क या अन्य शुल्क नहीं लगा सकते। रिपोर्ट में उद्धृत NPCI का कहना है कि यह केवल नीतिगत आश्वासन नहीं, अनुबंध और अनुपालन-कार्रवाई के माध्यम से लागू निर्देश है।

यह मुकदमे में NPCI का पक्ष है, न्यायालय द्वारा उसकी सभी दलीलें स्वीकार कर लेने का निर्णय नहीं। मूल हलफनामे की स्वतंत्र सार्वजनिक प्रति इस स्रोत-जाँच में नहीं मिली। शुल्क की वास्तविक आरंभ-तिथि, दर और लागू श्रेणी को केवल इस रिपोर्ट से निश्चित न मानें; ऊपर दिया NPCI का 13 अक्टूबर का वक्तव्य अलग से अधिसूचित तारीख की बात करता है।

शून्य शुल्क की नीति के लाभ

कम लागत से छोटे व्यापारियों और नए उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान अपनाने में मदद मिलती है। नकदी संभालने का खर्च घट सकता है और लेनदेन का रिकॉर्ड बन सकता है। भारतीय छोटे दुकानदार के लिए कुछ प्रतिशत भी महत्वपूर्ण लागत हो सकती है, विशेषकर कम लाभ-अंतर वाले व्यापार में।

लागत की स्थिरता का प्रश्न

साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायत-निवारण और लगातार उपलब्ध सेवा के लिए निवेश चाहिए। इस लागत को सरकार, बैंक, सेवा-प्रदाता, व्यापारी या दूसरे स्रोतों में कैसे बाँटा जाए, यही नीति का प्रश्न है। केवल अधिक लेनदेन होने से पर्याप्त आय बन ही जाएगी, यह जरूरी नहीं; दूसरी ओर लागत-वसूली का हर मॉडल समान रूप से समावेशी नहीं होगा।

अच्छे ढाँचे की कसौटियाँ

- **स्पष्टता:** लागू तिथि, पात्र व्यापारी और भुगतान-श्रेणी पहले से साफ हों।

- **अनुपात:** छोटे व्यापार और कम मूल्य भुगतान पर अनावश्यक बोझ न पड़े।
- **पारदर्शिता:** शुल्क, प्रोत्साहन और सार्वजनिक सहायता की वास्तविक लागत समझाई जाए।
- **गुणवत्ता:** लागत-वसूली का संबंध सुरक्षा, सेवा और शिकायत-निवारण के सुधार से हो।
- **समीक्षा:** उपयोग, नकदी की ओर वापसी और छोटे व्यापार पर असर की जाँच हो।

परीक्षा के लिए महत्त्व

UPI बहस सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना की स्थिरता और वित्तीय समावेशन को जोड़ती है। उत्तर में मुफ्त सेवा और लागत-रहित उत्पादन का भेद, हितधारकों के प्रोत्साहन तथा लक्षित सहायता की भूमिका स्पष्ट करें। प्रस्ताव, लागू व्यवस्था और न्यायालय के निर्णय को अलग रखें।

> पूँजी और वित्तीय ढाँचे का संबंधित अध्ययन: **LRS और विदेश निवेश का प्रश्न**

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

डिजिटल भुगतान की कम उपयोगकर्ता-लागत और भुगतान-तंत्र की वित्तीय स्थिरता में संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? UPI के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: UPI की उपयोगिता और MDR का संक्षिप्त परिचय दें।

मुख्य भाग में: समावेशन, छोटे व्यापारी, परिचालन लागत, सुरक्षा और सहायता-नीति का विश्लेषण करें। P2M/P2P तथा प्रस्ताव/लागू दर में अंतर रखें।

निष्कर्ष में: पारदर्शी, लक्षित और परिणाम-आधारित शुल्क-सहायता व्यवस्था की जरूरत बताएं।

स्रोत

- NPCI:13 अक्टूबर का आधिकारिक वक्तव्य
- 5 नवंबर: सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र का पक्ष
- The Hindu: Two days past Deepavali, NPCI yet to announce a date for UPI MDR rollout, 12 नवंबर 2026
- LiveLaw, 5 नवंबर 2026: NPCI के 3 नवंबर के जवाबी हलफनामे का विवरण
- न्यू इंडियन एक्सप्रेस, 5 नवंबर 2026: ग्राहक पर MDR न डालने संबंधी NPCI का पक्ष